ज्ञान, जुनून और जनसेवा का संगम
प्रो. तिलोत्तमा सिंह

नशा नहीं जीवन अपनाएं: डॉ. अखिल

उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट में बेटियां फिर अव्वल

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 49 | मूल्य 05 रुपये | 26 अप्रैल-02 मई, 2026

आप पर अपनों ने ही चलाई "झाड़ू"

दिव्य हिमगिरि

26 अप्रैल-02 मई, 2026

संपादक
डॉ. कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

संवाददाता
पूनम आर्या

विज्ञापन
सुनील सेमवाल

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*
*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

सड़कें बढ़ीं, सुरक्षा घटी

इसमें दोराय नहीं कि विकास में पिछड़े देश के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ के दुर्गम इलाकों में भी अब सड़कों का जाल बिछ गया है, जिससे वहां का कठिन जनजीवन का फी हद तक आसान हो गया है। मगर सड़कों के निर्माण के साथ-साथ सुरक्षित सफर का पहलू भी बेहद महत्त्वपूर्ण है। इस मसले पर शासन-प्रशासन के दावों के बावजूद सड़क हादसे कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले के चंबा क्षेत्र में बीते गुरुवार को एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार आठ लोगों की मौत हो जाने की घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा में खामियों और जोखिम को उजागर किया है। सवाल है कि यातायात नियमों का कड़ाई से पालन, सड़कों की समुचित देखरेख और निर्माण में कमियों पर गंभीरता से ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या सिर्फ कागजों में योजनाओं और उपायों का खाका खींचखीं ने भर से सड़क दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी? इन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय, राष्ट्री य राजमार्ग प्राधिकरण और सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को सड़क से सफर सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए थे। शीर्ष अदालत का यह कहना बेवजह नहीं था कि जिन खामियों को दुरुस्त किया जा सकता है, अगर उनकी वजह से सड़क हादसों में एक भी जान जाती है, तो यह संबंधित राज्य एवं प्राधिकरण की सुरक्षा जिम्मेदारी में कमी और लापरवाही को दर्शाता है। पहा ड़ी राज्यों में तो भौगोलिक जटिलताओं की दृष्टि से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम ज्यादा होता है और ऐसे में वहां हर स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। मगर शायद ही इस पर कोई विशेष ध्यान दिया जाता है और यही लापरवाही आए दिन पहाड़ी इलाकों में बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। बुनियादी सुरक्षा सावधानियों की कमी, सड़कों पर अतिक्रमण, ज्यादा जोखिम वाली जगहों पर पैराफिट की मजबूत घेराबंदी एवं निगरानी का अभाव खतरे को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि यातायात नियमों के पालन को सख्ती से लागू करा जाए। आधुनिक तकनीक-जैसे सीसीटीवी निगरानी, स्पीड गन और डिजिटल चालान-का अधिक उपयोग किया जाए और साथ ही, चालकों के प्रशिक्षण और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को भी अधिक कठोर और प्रभावी बनाना होगा। स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी अहम है। लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, जोखिमों के बारे में जानकारी देना और जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करना जरूरी है।

डॉ. कुँवर राज अस्थाना

नशा नहीं जीवन अपनाएं: डॉ. अखिल

देहरादून स्थित माइंड हील क्लिनिक वर्ष 2019 से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं (अवसाद, अनिंद्रा, नशा, एंग्जायटी) के उपचार की दिशा में कार्य कर रहा है। इस क्लिनिक से अब तक हजारों लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ है। लोकेश राज अस्थाना की माइंड हील क्लिनिक के कंसल्टेंट मनोचिकित्सक डॉ. अखिल चोपड़ा से उनकी मेडिकल जर्नी के बारे में बात हुई। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश...

अपनी पारिवारिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं।

मेरा जन्म पंजाब के जिला जालंधर के एक उच्च शिक्षित परिवार में हुआ है। मेरे पिताजी डाक्टर और माताजी शिक्षिका (फूड एंड न्यूट्रिशियन) रही है। परिवार में पढ़ाई का माहौल शुरू से ही रहा है। परिवार में ज्यादातर समय ज्ञान, विज्ञान और किताबों की बाते ही होती थी इसलिए शिक्षा के प्रति हमेशा झुकाव रहा है।

चिकित्सा क्षेत्र में आने के प्रेरणास्रोत्र कौन रहे है?

चिकित्सा के क्षेत्र में आने के लिए मेरे पिताजी ही मेरी प्रेरणास्रोत्र रहे है। चूंकि वे एक डॉक्टर थे और रोज उनके पास सैकड़ों मरीज आते थे और वापिस जाते समय चेहरे पर एक सुकून लेकर जाते थे इसलिए मैने भी तय कर लिया कि मुझे भी इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है और मैने 12वीं कक्षा के बाद मेडिकल में जाने की तैयारी शुरू कर दी। चूंकि सर्जिकल लाईन में मेरी शुरू से ही कोई खास रूचि नहीं थी इसलिए इंटरनशिप के दौरान जब मुझे मनोचिकित्सा को करीब से जानने का मौका मिला तो मेरी दिलचस्पी इसमें बढ़ती गई। यह एक अलग फील्ड था और इसमें कई तरह के लोगों से मिलना होता था और हर मरीज की प्रॉब्लम अलग तरीके की होती थी इसलिए मैने एमबीबीएस कम्पलीट करने के बाद अपना एमडी साईकेट्री में पूर्ण किया।

अपने प्रोफेशनल सफर के बारे में बताए और आपकी अब तक की क्या-क्या उपलब्धियां रही है?

गुरू गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज, फरीदकोट, पंजाब से मैने अपना एमबीबीएस पूर्ण किया। दयानन्द मेडिकल कॉलेज लुधियाना से मैने एमडी साईकेट्री किया। दयानन्द मेडिकल कॉलेज, लुधियाना में बतौर एसआर (सीनियर रेजीडेंट) 2 साल कार्य किया। उसके बाद कुछ समय जालंधर के एक नशा मुक्ति केंद्र के साथ कार्य किया। वर्ष 2016 में देहरादून में सुभारती मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। सुभारती मेडिकल कॉलेज के साईकेट्री डिपार्टमेंट को धीरे-धीरे विकसित किया। गांवों में मेडिकल कॉलेज के कैम्प करवाए। आस-पास के नशा मुक्ति केंद्रों को कॉलेज के साथ जोडा। डिप्रेशन, तनाव, नशा इत्यादि के बारे में लोगों को जागरूक किया। वर्ष 2019 में माइंड हील के नाम से अपना क्लिनिक शुरू किया। वर्तमान में हमारे दो क्लिनिक कार्य कर रहे है। मेरी पत्नी डॉ. दिव्या घई भी एक मनोचिकित्सक है और वे जीएमएस रोड स्थित माइंड हील क्लिनिक का संचालन करती है और मैं निरंजनपुर आईटीआई के सामने स्थित माइंड हील प्लस क्लिनिक का संचालन करता हूँ। हमारे द्वारा स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों का भी समय-समय पर आयोजन किया जाता है। कोविड काल (वर्ष 2021) में अमर उजाला द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।

चिकित्सा के क्षेत्र में आपका कोई यादगार अनुभव।

चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे अनुभव हुए है। अच्छा लगता है जब कोई आकर आपको दिल से शुक्रिया करता है। उनको लगता है कि हमारी वजह से उनके जीवन में बहुत बडा बदलाव आया है। मेरी दो यंग फीमेल पेशेंट ऐसी थी जिनको शादी से पहले कुछ मानसिक समस्या थी और उनको लगता था कि वे प्रेगनेंसी नहीं कर पाएंगी लेकिन हमारे ईलाज से उनको इतना असर हुआ कि उनकी एक हेल्थी प्रेगनेंसी हुई और वो हमारे क्लिनिक आकर हमको धन्यवाद देकर गई। कई बार लोग अपने घरों से बना सामान लेकर आते है। इससे अच्छा अनुभव और क्या होगा कि हम हमारे क्लिनिक द्वारा लोगों के जीवन को सुधार रहे है।

दिव्य हिमगिरी के पाठकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?

पाठकों के लिए मेरा संदेश है कि वे अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज की भागदौड भरी जिदंगी में हम सारी चीजों को महत्ता देते है लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को इगनोर करते है जबकि इस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब मन स्वस्थ होगा तभी शरीर भी सही रूप से कार्य करेगा। इसके अलावा नशे से दूर रहे क्योंकि नशा आपकी और आपके परिवार की जिदंगी और समाज को बर्बाद कर सकता है। इसलिए नशा नहीं जीवन अपनाएं।

"सदन में महिला आरक्षण नहीं, मोदी संरक्षण बिल गिरा है"- शिल्पी अरोड़ा

नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन बिल के संसद में पारित न होने पर आपका क्या मत है?

"सदन में महिला आरक्षण नहीं, बल्कि मोदी संरक्षण बिल गिरा है।" महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पूर्ण बहुमत से पारित हो चुका था, जो यह दर्शाता है कि संसद और सभी दल इस मुद्दे पर सहमत थे। इसके बावजूद, केंद्र सरकार ने इसे लागू करने में गंभीरता नहीं दिखाई और 16 अप्रैल 2026 को अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार इसे नोटिफाई किया। यह महिलाओं के साथ "छल" और "राजनीतिक धोखा" है। सरकार जानबूझकर जनगणना और परिसीमन का बहाना बनाकर इस कानून के क्रियान्वयन में देरी कर रही है। जबकि वास्तविकता यह है कि यदि सरकार की नीयत साफ होती, तो 543 सदस्यीय वर्तमान लोकसभा संरचना के भीतर ही महिला आरक्षण लागू किया जा सकता था। पांच साल तक इस मुद्दे को टालना यह साबित करता है कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति गंभीर नहीं है, बल्कि इसे चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल कर रही है।

जब महिला आरक्षण 2023 में पास हो चुका है, तो क्या कांग्रेस केंद्र सरकार पर इसे आगामी लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने के लिए दबाव बनाएगी?

कांग्रेस पार्टी शुरू से ही महिला आरक्षण की प्रबल समर्थक रही है और आगे भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद रखेगी। कांग्रेस ने लगातार मांग की थी कि महिला आरक्षण को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू किया जाए, ताकि महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व मिल सके। कांग्रेस केंद्र सरकार पर राजनीतिक और लोकतांत्रिक दोनों स्तरों पर दबाव बनाएगी, ताकि इस कानून को बिना किसी देरी के लागू किया जाए। यदि कानून को तुरंत लागू करने के लिए किसी संशोधन की आवश्यकता है, तो सरकार को उसे तत्काल करना चाहिए। केवल प्रक्रियात्मक कारणों का हवाला देकर इसे टालना उचित नहीं है। महिला आरक्षण केवल एक कानून नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी को न्याय देने का माध्यम है और इसे लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है।

कांग्रेस परिसीमन बिल के विरोध में क्यों है?

कांग्रेस परिसीमन की प्रक्रिया के मूल सिद्धांत के खिलाफ नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा इसके राजनीतिक दुरुपयोग का विरोध करती है। परिसीमन का असली उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना होता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में भाजपा इसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। यह "छुपा हुआ एजेंडा" है, जिसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे सत्ता पक्ष को फायदा हो। कांग्रेस का मानना है कि परिसीमन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया व्यापक परामर्श, पारदर्शिता और सभी राजनीतिक दलों की सहमति से ही होनी चाहिए। यदि इसे एकतरफा तरीके से लागू किया गया, तो यह लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर सकता है।

कांग्रेस का स्पष्ट रुख एवं मांगें क्या हैं?

हमारा स्पष्ट रूख है कि महिला आरक्षण का पूर्ण समर्थन देना और तत्काल क्रियान्वयन की मांग, 2024 के लोकसभा चुनाव से ही इसे लागू किया जाना चाहिए था। आवश्यकता पड़ने पर तत्काल संशोधन किया जाए, मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा संरचना में भी इसे लागू किया जा सकता है

OBC आरक्षण और जातिगत जनगणना पर कांग्रेस का क्या मत है?

कांग्रेस महिला आरक्षण में OBC महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की पक्षधर है। इसके लिए जातिगत जनगणना आवश्यक है, ताकि SC, ST और OBC वर्ग की महिलाओं को न्यायपूर्ण और समान प्रतिनिधित्व मिल सके। बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों में यह प्रक्रिया कुछ महीनों में पूरी की जा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार इसे जानबूझकर टाल रही है।

भाजपा सरकार ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर यू-टर्न लिया है- कृषि कानूनों को किसानों के लंबे आंदोलन के बाद वापस लेना पड़ा, GST के गलत क्रियान्वयन से जनता पर बोझ पड़ा और बाद में बदलाव करने पड़े, और अब जातिगत जनगणना को भी टाला जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार बिना होमवर्क के किसी छुपी हुई ताकतों के ईशारों पर का कर रही है। हाथरस, उन्नाव, अंकिता भंडारी और मणिपुर जैसे मामलों यह दर्शाने के लिए काफी है कि देश में महिला सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक है। कई मामलों में दोषियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता दिखाई देता है, जो बेहद गंभीर विषय है। साथ ही महंगाई, उर्वरकों पर GST और बढ़ते घरेलू खर्च का सबसे अधिक असर महिलाओं पर पड़ रहा है, जिससे उनका जीवन और अधिक कठिन हो गया है। महिला आरक्षण को लेकर देरी, महिला सुरक्षा के मुद्दों पर विफलता और बढ़ती महंगाई के लिए प्रधानमंत्री को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए।

आप दिव्य हिमगिरि के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी

मेरा यही संदेश है कि महिलाओं को राजनीति का हथियार बनाना बंद करें। महिला आरक्षण तुरंत लागू करें-यह राष्ट्रहित और देशहित में है- पूरा देश आपकी ओरदेख रहा है।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने नारी सशक्तिकरण को हकीकत में बदला- मधु भट्ट

परिसीमन बिल और उससे जुड़ा नारी शक्ति वंदन बिल संसद में पास नहीं हो पाया, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं?

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण बिल) वास्तव में संसद के दोनों सदनों से 2023 में पारित हो चुका है, लेकिन इसका कार्यान्वयन तुरंत नहीं होगा। इसे लागू करने की शर्तें हैं: अगली जनगणना के बाद, उसके आधार पर परिसीमन होने के बाद। परिसीमन का मतलब है- लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। इसलिए, यह कहना कि बिल "पास नहीं हुआ" पूरी तरह सही नहीं है। असल मुद्दा यह है कि इसे लागू होने में देरी होगी, जो एक राजनीतिक और व्यावहारिक दोनों तरह का प्रश्न है। एक दृष्टिकोण से यह एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि पहली बार 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। दूसरे दृष्टिकोण से इसे लागू करने में देरी इसे केवल "प्रतीकात्मक" बना सकती है।

विपक्ष आखिर क्यों नारी शक्ति वंदन बिल के खिलाफ है?

विपक्ष का विरोध "महिला आरक्षण" के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके डिजाइन और टाइमिंग को लेकर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार तुरंत लागू कर सकती थी, लेकिन इसे जनगणना और परिसीमन से जोड़कर अनिश्चित भविष्य में डाल दिया गया। कई दल (जैसे राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी) चाहते हैं कि महिलाओं के भीतर भी OBC कोटा हो। विपक्ष मानता है कि यह कदम चुनावी लाभ के लिए है, न कि तुरंत सशक्तिकरण के लिए। कुल मिलाकर, विरोध "महिलाओं को आरक्षण देने" पर नहीं, बल्कि कैसे और कब दिया जाए, इस पर है।

भाजपा राजनीति में महिलाओं के उत्थान एवं सम्मान के लिए क्या रणनीती अपना रही है?

भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बहु-आयामी है-सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण भी।

1. राजनीतिक प्रतिनिधित्व

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (33% आरक्षण) पार्टी के भीतर महिलाओं को टिकट देने पर जोर

2. कल्याणकारी योजनाएं

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-मुफ्त LPG कनेक्शन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा और जागरूकता, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता

3. आर्थिक सशक्तिकरण

महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) को बढ़ावा, मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को लोन

4. सामाजिक-सांस्कृतिक संदेश

"नारी शक्ति" को राजनीतिक और सांस्कृतिक दंततंजपअम का हिस्सा बनाना

संक्षेप में निष्कर्ष- बिल पास हो चुका है, लेकिन लागू होने में समय लगेगा, यही असली विवाद है। विपक्ष की आपत्तियाँ प्रक्रिया और समावेशिता को लेकर हैं। भाजपा इसे एक बड़े 'women empowerment agenda' के हिस्से के रूप में पेश कर रही है। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को दशकों तक सिर्फ राजनीतिक नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने इसे हकीकत में बदलकर संसद से पास करवाया, यही सबसे बड़ा अंतर है। जहाँ तक परिसीमन की बात है, परिसीमन कोई राजनीतिक खेल नहीं, बल्कि एक संवैधानिक आवश्यकता है। बिना सही जनगणना और परिसीमन के आरक्षण लागू करना न तो न्यायसंगत होगा, न ही टिकाऊ। भाजपा स्थायी और पारदर्शी समाधान चाहती है, न कि जल्दबाजी में लिया गया अधूरा फैसला।

अब विपक्ष के विरोध की सच्चाई भी समझ लीजिए- जो पार्टियाँ आज सवाल उठा रही हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी, उन्होंने अपने शासनकाल में महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए क्या किया? वास्तव में, ये दल महिला सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं।

भाजपा की सोच साफ है- महिलाओं को सिर्फ राजनीति में सीट नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक शक्ति भी मिले। यही वजह है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से सामाजिक सोच बदली और अब नारी शक्ति वंदन से नीति निर्माण में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है

आप दिव्य हिमगिरि के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी

भाजपा वादे नहीं करती, निर्णय लेती है और उन्हें जमीन पर उतारती है। नारी शक्ति वंदन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और विपक्ष की बेचैनी ही इस बात का सबूत है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

आम आदमी पार्टी के भीतर उठा सियासी तूफान खुलकर सामने आ गया। पार्टी के प्रमुख और प्रभावशाली चेहरों में शामिल राघव चड्ढा ने अपने छह राज्यसभा साथियों के साथ अचानक इस्तीफा देकर न सिर्फ संगठन को बड़ा झटका दिया है, बल्कि राजनीतिक समीकरण भी बदल दिए हैं। उनके साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और राजिंदर गुप्ता जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। 24 अप्रैल को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का ऐलान करते हुए चड्डा ने साफ कहा कि पार्टी अब अपने मूल सिद्धांतों और विचारधारा से भटक चुकी है। उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा में आप के दो-तिहाई सांसद उनके साथ हैं और वे संविधान के प्रावधानों के तहत भाजपा में विलय की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। इस घटनाक्रम ने आप के भीतर गहरी दरार को उजागर कर दिया है और साफ संकेत दिया है कि पार्टी के भीतर असंतोष अब बगावत में बदल चुका है, जिसका सीधा सियासी फायदा भाजपा को मिलता दिख रहा है।

आम आदमी पार्टी की सियासत इन दिनों अपने सबसे बड़े अंदरूनी संकट से गुजरती दिख रही है। एक ऐसा संकट, जिसने न सिर्फ पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को झकझोर दिया है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी नए समीकरणों की आहट पैदा कर दी है। बीते कुछ वर्षों में आप ने जिस तेजी से अपनी पहचान बनाई, उसी तेजी से अब उसके भीतर दरारें भी गहराती नजर आ रही हैं। शुक्रवार, 24 अप्रैल को जो घटनाक्रम सामने आया, उसने इस सियासी हलचल को सार्वजनिक कर दिया। पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल राघव चड्डा का अपने छह राज्यसभा साथियों के साथ अचानक इस्तीफा देना केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले ने यह साफ कर दिया कि पार्टी के भीतर असंतोष अब उस स्तर तक पहुंच चुका है, जहां संवाद की गुंजाइश खत्म होती दिख रही है। दिल्ली से लेकर पंजाब और राष्ट्रीय स्तर तक आप ने खुद को एक वैकल्पिक राजनीतिक ताकत के रूप में पेश किया था। लेकिन अब वही पार्टी अपने ही नेताओं के असंतोष और अलगाव की कहानी बनती नजर आ रही है। चड्डा के साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और राजिंदर गुप्ता जैसे नामों का एक साथ पार्टी छोड़ना इस बात का संकेत है कि यह फैसला व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक असहमति का परिणाम है। कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चड्डा ने जिस तरह से पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए, उसने पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया। उन्होंने साफ कहा कि आप अब अपने मूल सिद्धांतों और विचारधारा

एक दिन में बदली सियासत, आप के सामने सबसे बड़ी चुनौती

भाजपा की ओर से अभी औपचारिक बयान भले सीमित हो, लेकिन अंदरखाने इस घटनाक्रम को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। दूसरी ओर, आप के लिए यह समय आत्ममंथन का है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने संगठन को कैसे संभाले और कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास बनाए रखे। लगातार हो रहे पलायन से यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या पार्टी अपने मूल एजेंडे और विचारधारा को बनाए रखने में सफल रही है या नहीं। पार्टी के कुछ नेताओं ने इस घटनाक्रम को "राजनीतिक अवसरवाद" बताया है, जबकि अन्य इसे "अंदरूनी असंतोष का परिणाम" मान रहे हैं। हालांकि, सच्चाई जो भी हो, इतना तय है कि इस घटनाक्रम ने आप की छवि पर असर डाला है। सोशल मीडिया और जनमानस में भी इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां एक वर्ग इसे पार्टी की कमजोरी के रूप में देख रहा है, वहीं दूसरा वर्ग इसे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मान रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आप इस संकट से उबरकर खुद को फिर से मजबूत कर पाती है या यह घटनाक्रम उसके लिए एक लंबी राजनीतिक चुनौती बन जाता है। वहीं भाजपा के लिए यह एक अवसर है, जिससे वह अपने प्रभाव को और मजबूत कर सकती है। 24 और 25 अप्रैल के बीच हुए इस घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। एक दिन में हालात कैसे बदल सकते हैं, इसका यह ताजा उदाहरण है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आगे की रणनीति क्या होगी और यह सियासी उठापटक किस दिशा में जाएगी।

से भटक चुकी है। उनके मुताबिक, जिस राजनीति के आदर्शों के साथ उन्होंने पार्टी जॉइन की थी, वह अब कहीं पीछे छूट चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक के बाद एक बड़े चेहरों का पार्टी से अलग होना यह दिखाता है कि संगठन के भीतर संवाद और संतुलन की कमी रही है। पहले भी कई संस्थापक और वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन इस बार मामला सीधे संसद तक पहुंच गया है, जो आप के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करता है। 25 अप्रैल तक आते-आते इस घटनाक्रम ने और रफ्तार पकड़ ली। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी छोड़ने वाले सांसदों ने औपचारिक रूप से अपने निर्णय की जानकारी राज्यसभा अध्यक्ष को दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने संविधान के तहत भाजपा में विलय की प्रक्रिया शुरू करने का दावा भी किया है। अगर यह प्रक्रिया पूरी होती है, तो यह आप के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ सत्ता या पद का मामला नहीं है, बल्कि पार्टी की आंतरिक संरचना और नेतृत्व शैली से जुड़ा हुआ है। कई नेताओं को लंबे समय से निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और केंद्रीय नेतृत्व के बढ़ते नियंत्रण को लेकर आपत्ति थी। यह असंतोष धीरे-धीरे बढ़ता गया और अब एक बड़े विस्फोट के रूप में सामने आया है। इस घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे भाजपा को सीधा राजनीतिक लाभ मिलता नजर आ रहा है। जहां आप अपने अंदरूनी संकट से जूझ रही है, वहीं भाजपा इसे अपने विस्तार के अवसर के रूप में देख रही है। खासकर राज्यसभा में संख्या बल के लिहाज से यह बदलाव आने वाले समय में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

अंदरूनी नाराजगी, अनदेखी और टकराव ने बढ़ाई दूरी

आम आदमी पार्टी में हाल ही में हुए बड़े सियासी घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी के भीतर असंतोष लंबे समय से पनप रहा था। अचानक सात राज्यसभा सांसदों का एक साथ पार्टी छोड़ना कोई एक दिन का फैसला नहीं, बल्कि कई महीनों से चल रही नाराजगी, अनदेखी और नेतृत्व से टकराव का नतीजा है। पार्टी के भीतर संवाद की कमी, जिम्मेदारियों में बदलाव और व्यक्तिगत मतभेद धीरे-धीरे इतने गहरे हो गए कि आखिरकार यह बगावत के रूप में सामने आया। आप की तेजी से बढ़ती राजनीति के बीच संगठनात्मक संतुलन बनाए रखना चुनौती बन गया था। कई वरिष्ठ नेताओं को लगा कि उनकी भूमिका सीमित कर दी गई है और निर्णय प्रक्रिया में उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा। यही कारण है कि अलग-अलग कारणों से नाराज चल रहे नेताओं ने एक साथ बड़ा कदम उठा लिया। राघव चड्डा- राघव चड्डा की नाराजगी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ रिश्तों में आई खटास से जुड़ी बताई जा रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय उनकी चुप्पी और विदेश में रहने को लेकर पहले ही सवाल उठे थे। इसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटा दिया और उन्हें बोलने का समय भी कम मिलने लगा। पार्टी के भीतर उनके खिलाफ माहौल बनने से वे खुद को अलग-थलग महसूस करने लगे, जिसने उनके फैसले को प्रभावित किया। संदीप पाठक- डॉ. संदीप पाठक लंबे समय तक पार्टी की रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाते रहे। पंजाब, गोवा और गुजरात में संगठन को मजबूत करने में उनका बड़ा योगदान रहा। लेकिन हाल के समय में उन्हें प्रमुख बैठकों और फैसलों से दूर रखा जाने लगा। पंजाब की जिम्मेदारी उनसे लेकर दूसरे नेता को सौंपना भी उनकी नाराजगी की बड़ी वजह बना। स्वाति मालीवाल- स्वाति मालीवाल का विवाद सीधे शीर्ष नेतृत्व से जुड़ा रहा। उन्होंने वैभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। इसके बाद से उनका पार्टी से मोहभंग बढ़ता गया और वे सार्वजनिक रूप से भी विरोध जताने लगीं। अशोक मित्तल- अशोक मित्तल को राज्यसभा में अहम जिम्मेदारी मिलने के बावजूद, जब उनके ठिकानों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई हुई तो पार्टी का समर्थन न मिलना उनके लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इस दौरान खुद को अकेला महसूस करने की वजह से उन्होंने दूरी बना ली। हरभजन सिंह- हरभजन सिंह को राज्यसभा सदस्य बनाए जाने के बाद भी पार्टी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका नहीं मिली। उन्हें निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा गया, जिससे वे लगातार अलग-थलग महसूस करते रहे। राजिंदर गुप्ता- राजिंदर गुप्ता, जो उद्योग जगत से जुड़े बड़े नाम हैं, पार्टी में सक्रिय भूमिका नहीं निभा सके। राज्यसभा सदस्य बनने के बावजूद उन्हें संगठनात्मक स्तर पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दी गई, जिससे उनकी दूरी बढ़ती गई। विक्रमजीत सिंह साहनी- विक्रमजीत सिंह साहनी भी लंबे समय से

पार्टी में सक्रिय थे, लेकिन उन्हें भी पार्टी फोरम में अपेक्षित महत्व नहीं मिला। यही कारण रहा कि उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का फैसला किया। कुल मिलाकर, इन सभी नेताओं के अलग-अलग कारण जरूर रहे, लेकिन एक बात समान रही, पार्टी के भीतर संवाद की कमी और नेतृत्व से बढ़ती दूरी। यही कारण है कि यह सामूहिक इस्तीफा आप के लिए अब तक का सबसे बड़ा सियासी झटका बन गया है।

सांसदों के पाला बदलने पर गरमाई सियासत, केजरीवाल ने बताया 'पंजाब के साथ धोखा'

आम आदमी पार्टी में सात राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह कदम पंजाब और पंजाबियों के साथ बड़ा धोखा है। केजरीवाल ने अपने संदेश में आरोप लगाया कि यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया है और इसका उद्देश्य पंजाब की राजनीति को प्रभावित करना है। उन्होंने साफ कहा कि जनता ऐसे कदम उठाने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। पार्टी की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि पंजाब के जनादेश के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि जनता इसका जवाब समय आने पर जरूर देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिलने का समय मांगा है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री मान सभी विधायकों के साथ दिल्ली जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में पार्टी बदलने वाले सांसदों के खिलाफ 'राइट टू रिकॉल' की मांग उठाई जाएगी। मुख्यमंत्री मान इस मुद्दे पर विस्तार से अपना पक्ष रखेंगे और संवैधानिक कार्रवाई की मांग करेंगे। दूसरी ओर, पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह भी उपराष्ट्रपति से मिलने की तैयारी में हैं। वह उन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे, जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। हालांकि, पार्टी के कुछ नेताओं का दावा है कि सभी सात सांसदों ने अभी आधिकारिक रूप से पक्ष नहीं बदला है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल केवल तीन सांसद ही भाजपा में शामिल हुए हैं, जबकि बाकी चार अब भी आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी इसे विश्वासघात बता रही है, वहीं दूसरी ओर आगे की कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के संकेत भी साफ नजर आ रहे हैं।

उत्तराखंड में बाघ का बढ़ता आतंक, ग्रामीणों की जान खतरे में

यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में बाघ का आतंक लगातार बढ़ रहा है। जनपदों के दूरस्थ गांवों में आए दिन ऐसी घटनाएँ सामने आ रही हैं, जहाँ बाघ ग्रामीणों को अपना निवाला बना रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि शासन और प्रशासन की संवेदनशीलता कहीं दिखाई नहीं देती। श्री आर्य ने कहा कि क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गई है? क्या ग्रामीणों की जान की कोई कीमत नहीं है? आज हालत यह है कि लोग जंगल जाने से डर रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं और महिलाएं रोज मौत का सामना कर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह केवल वन्यजीव संरक्षण का विषय नहीं है, यह मानव जीवन की सुरक्षा का प्रश्न है। हम बाघ को बचाना चाहते हैं- यह हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या इंसान की जान उससे कम महत्वपूर्ण है?

श्री आर्य ने कहा कि मैं सरकार से कुछ स्पष्ट मांगें रखना चाहता हूँ-

संवेदनशील क्षेत्रों में तुरंत विशेष निगरानी और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। हर प्रभावित क्षेत्र में रैपिड रिस्पॉन्स टीम तैनात की जाए। ग्रामीणों के लिए सुरक्षा उपकरण और जागरूकता अभियान चलाए। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उन्हें तत्काल और सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए और सबसे महत्वपूर्ण कि स्थानीय लोगों की आवाज को नीति का हिस्सा बनाया जाए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार अगर आज भी नहीं जागी, तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं होगी, यह मानवीय संवेदनाओं की हार होगी।

श्रीगोपाल नारसन को स्वामी विवेकानंद पर्सनलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड!

रुड़की- विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के उपकुलपति एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. श्रीगोपाल नारसन स्वामी विवेकानंद पर्सनलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए मिला है। श्रीगोपाल नारसन को हाल ही में विगत 11 वर्षों से प्रतिदिन एक आध्यात्मिक कविता लिखने व उपभोक्ता कानून जागरूकता के लिए उनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन हैड डॉ लिवान जसिनिया व इंटरनेशनल चेयरमैन डा. डी. साकुंडे द्वारा जारी प्रमाण पत्र में श्रीगोपाल नारसन की उक्त उपलब्धि के लिए प्रसंशा की गई। श्रीगोपाल नारसन प्रतिदिन ब्रह्माकुमारीज विचारों से प्रेरित आध्यात्मिक एवम सदाचरण से जुड़ी 12 पंक्तियों की कविता अमृतबेला में सुबह 4 बजे लिखते है और 11 वर्षों में कभी ऐसा नही हुआ जो उनसे कविता लिखने का क्रम छुटा हो, इसे एक रिकॉर्ड मानते हुए ही उनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसी के साथ वे उपभोक्ता जागरूकता अभियान भी निरंतर चला रहे है। वही अब उन्हें उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद पर्सनलिटी ऑफ द ईयर सम्मान मिलना एक बड़ी उपलब्धि है।

उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट में बेटियां फिर अव्वल

उत्तराखंड में उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिनमें इस बार भी बेटियों का दबदबा साफ नजर आया। हाईस्कूल का कुल परिणाम 92.10% रहा, जिसमें बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 96.07% और बालकों का 88.03% दर्ज किया गया। वहीं इंटरमीडिएट का कुल परिणाम 85.11% रहा, जहां बालिकाओं का पास प्रतिशत 88.09% और बालकों का 81.93% रहा। हाईस्कूल में एमपी हिंदू इंटर कॉलेज, रामनगर (नैनीताल) के अक्षत गोपाल ने 98.20% अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया, जबकि ईशान कोठारी (उत्तरकाशी) और जीआईसी खेरना, नैनीताल की भूमिका पांडे 98% अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। इंटरमीडिएट में सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज, बागेश्वर की गीतिका पंत और भंजूराम अमर इंटर कॉलेज, भूरारानी (उधम सिंह नगर) की सुशीला मेहंदीरत्ता ने 98% अंक के साथ संयुक्त रूप से टॉप किया, जबकि सरस्वती विद्या मंदिर, ऋषिकेश के आर्यन दूसरे और मायापुर हरिद्वार की वंशिका तीसरे स्थान पर रहीं। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सभी सफल छात्र-छात्राओं को बधाई दी।

उत्तराखंड में शनिवार, 25 अप्रैल का दिन लाखों छात्र-छात्राओं और उनके परिवारों के लिए बेहद अहम और यादगार बन गया। महीनों की मेहनत, तनाव और इंतजार के बाद आखिरकार वह घड़ी आ गई जब बोर्ड परीक्षा के नतीजों ने छात्रों के भविष्य की दिशा तय कर दी। सुबह से ही छात्र-छात्राएं अपने-अपने परिणाम जानने के लिए उत्सुक नजर आए, वहीं अभिभावकों और शिक्षकों की निगाहें भी इस पर टिकी रहीं कि इस बार प्रदर्शन कैसा रहेगा। हर साल की तरह इस बार भी रिजल्ट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रहा, बल्कि इसमें मेहनत, संघर्ष और सपनों की कहानी साफ झलकती नजर आई। खास बात यह रही कि एक बार फिर बेटियों ने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया और यह साबित कर दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में वे किसी से पीछे नहीं हैं। राज्यभर में कई ऐसे छात्र-छात्राएं सामने आए, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद बेहतरीन अंक हासिल कर मिसाल पेश की। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में शिक्षा के स्तर में जो निरंतर सुधार देखने को मिला है, उसका असर इस बार के परिणामों में भी साफ दिखाई दिया। बेहतर परीक्षा प्रबंधन, डिजिटल प्रक्रियाओं का विस्तार और शिक्षकों की मेहनत ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई है। इसी सकारात्मक माहौल के बीच उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने शनिवार को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया। इस बार का रिजल्ट कई मायनों में खास रहा जहां एक ओर कुल पास प्रतिशत में सुधार दर्ज किया गया, वहीं दूसरी ओर बेटियों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। हाईस्कूल परीक्षा में इस वर्ष कुल परिणाम 92.10 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। आंकड़ों के अनुसार बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 96.07 रहा, जबकि बालकों का पास प्रतिशत 88.03 दर्ज किया गया। इससे साफ है कि लड़कियों ने एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित की है।

इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम भी उत्साहजनक रहा, जहां कुल 85.11 प्रतिशत छात्र-छात्राएं सफल हुए। यहां भी बालिकाओं ने बाजी मारी उनका पास प्रतिशत 88.09 रहा, जबकि लड़कों का 81.93 प्रतिशत रहा। यह लगातार बढ़ती शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा और बेटियों की मजबूत तैयारी को दर्शाता है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सफल छात्रों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने असफल विद्यार्थियों को निराश न होने और दोबारा मेहनत के साथ प्रयास करने का संदेश दिया। अगर हाईस्कूल टॉपर्स की बात करें तो रामनगर (नैनीताल) स्थित एमपी हिंदू इंटर कॉलेज के छात्र अक्षत गोपाल ने 500 में से 491 अंक (98.20%) प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। वहीं उत्तरकाशी के ईशान कोठारी और नैनीताल के जीआईसी खेरना की छात्रा भूमिका पांडे ने 490 अंक (98%) के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान

इंटरमीडिएट में बागेश्वर ने दोहराई सफलता की कहानी

इंटरमीडिएट परीक्षा में भी सफलता की कहानी लगभग वैसी ही रही। इस बार कुल परिणाम 85.11 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.88 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि बताती है कि राज्य में शिक्षा का स्तर लगातार सुधर रहा है। टॉपर्स की सूची में सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज, बागेश्वर की गीतिका पंत और उधम सिंह नगर की सुशीला मेहंदीरत्ता ने 490/500 अंक (98%) हासिल कर संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर ऋषिकेश के आर्यन रहे, जिन्होंने 489 अंक (97.80%) प्राप्त किए, जबकि हरिद्वार की वंशिका ने 485 अंक (97%) के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इंटरमीडिएट में भी बागेश्वर जिला 94.81 प्रतिशत परिणाम के साथ राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। परीक्षा में कुल 1,02,986 छात्र पंजीकृत थे, जिनमें से 1,00,452 ने परीक्षा दी और 85,499 छात्र-छात्राएं सफल हुए। परिणाम के विश्लेषण में यह भी सामने आया कि 7,814 छात्र सम्मान सहित उत्तीर्ण हुए, जबकि 41,507 छात्र प्रथम श्रेणी में पास हुए। द्वितीय श्रेणी में 34,987 और तृतीय श्रेणी में केवल 330 छात्र ही रहे, जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है। इस बार परीक्षा प्रक्रिया भी काफी व्यवस्थित और समयबद्ध रही। प्रयोगात्मक परीक्षाएं 13 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित की गईं, जबकि लिखित परीक्षाएं फरवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू होकर 20 मार्च तक चलीं। पूरे प्रदेश में 1,261 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 50 एकल और 1,211 मिश्रित केंद्र शामिल थे। सुरक्षा के लिहाज से 156 केंद्रों को संवेदनशील और 6 को अति संवेदनशील घोषित किया गया था। टिहरी गढ़वाल में सबसे अधिक 136 केंद्र बनाए गए, जबकि चंपावत में सबसे कम 44 केंद्र रहे। इस साल एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला, पहली बार आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कराई गई, जिससे छात्रों को काफी सहूलियत मिली। साथ ही, स्कूलों को अलग-अलग पोर्टल और पासवर्ड उपलब्ध कराए गए, ताकि छात्र अपने विद्यालय में ही आसानी से परिणाम देख सकें। छात्र अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल पारदर्शिता और सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम न केवल बेहतर आंकड़ों का संकेत देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि राज्य में शिक्षा का स्तर लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। बेटियों का शानदार प्रदर्शन इस बदलाव की सबसे मजबूत तस्वीर पेश करता है, जो आने वाले समय में और भी सकारात्मक परिणामों की उम्मीद जगाता है।

प्राप्त किया। खास बात यह रही कि भूमिका पांडे ने बालिकाओं की मेरिट सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर बेटियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को और मजबूत किया। बागेश्वर के योगेश जोशी ने 489 अंक (97.80%) हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। जिला स्तर पर भी इस बार बागेश्वर ने शानदार प्रदर्शन किया। हाईस्कूल में बागेश्वर जिला 96.98 प्रतिशत परिणाम के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। कुल 1,08,983 परीक्षार्थियों में से 1,00,373 छात्र-छात्राएं सफल हुए, जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार का संकेत है।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सफल विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित होते ही पूरे प्रदेश में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। हजारों छात्र-छात्राओं की मेहनत रंग लाई और उन्होंने सफलता हासिल कर अपने परिवार और राज्य का नाम रोशन किया। इस खास मौके पर राज्य के शीर्ष नेतृत्व ने भी विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जहां एक ओर सफल छात्र-छात्राओं को बधाइयों का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी ओर उन छात्रों का भी हौसला बढ़ाया जा रहा है, जिन्हें इस बार अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाया। इसी क्रम में गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सफल सभी छात्र-छात्राओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने इसे न केवल विद्यार्थियों बल्कि उनके अभिभावकों, गुरुजनों और पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय बताया। राज्यपाल ने माता-पिता और शिक्षकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन, प्रेरणा और निरंतर सहयोग से ही छात्र इस मुकाम तक पहुंच सके हैं। साथ ही उन्होंने उन विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित किया, जिन्हें इस बार सफलता नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि असफलता जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि यह सीखने और आगे बढ़ने का अवसर होती है। आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ दोबारा प्रयास करने पर सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि विद्यार्थियों के निरंतर परिश्रम, अनुशासन और अटूट संकल्प का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यही लगन और आत्मविश्वास उन्हें जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।

मुख्यमंत्री ने उन छात्रों के लिए भी प्रेरणादायक संदेश दिया, जिन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। उन्होंने कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि धैर्य, सकारात्मक सोच और लगातार प्रयास के साथ वे भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सफल विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी बधाई दी और उनके सहयोग को सराहा। इस तरह उत्तराखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने मिलकर विद्यार्थियों को न सिर्फ उनकी सफलता पर बधाई दी, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित भी किया। यह संदेश प्रदेश के युवाओं के लिए नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करने वाला साबित हो रहा है।

महिला सशक्तिकरण पर धामी सरकार की तैयारी

उत्तराखंड की राजनीति में 28 अप्रैल का दिन खास होने जा रहा है, जब विधानसभा के विशेष सत्र में महिलाओं से जुड़े एक अहम विधेयक पर चर्चा होगी। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार 'नारी शक्ति वंदन बिल' को पेश करने की तैयारी में है, जिसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। देहरादून में होने वाले इस सत्र को लेकर प्रशासनिक और सुरक्षा स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सरकार इसे अपनी प्रमुख उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत करना चाहती है, वहीं विपक्ष इसके प्रावधानों पर सवाल उठाने के संकेत दे रहा है। ऐसे में सदन में तीखी बहस की संभावना बनी हुई है। महिलाओं में इस बिल को लेकर खास उत्साह है और उन्हें उम्मीद है कि इससे उनके अधिकारों और अवसरों में बढ़ोतरी होगी। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट।

उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने की तैयारी नजर आ रही है। पहाड़ की राजनीति में अक्सर विकास, पलायन और रोजगार जैसे मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन इस बार केंद्र में महिलाएं हैं। राज्य सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाला समय महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को मजबूत करने का होगा। गर्म होते राजनीतिक माहौल के बीच सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, जो न सिर्फ नीतिगत बदलाव का संकेत देता है, बल्कि सामाजिक संरचना पर भी असर डाल सकता है। गांव से लेकर शहर तक, महिला समूहों और सामाजिक संगठनों में इस पहल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खासकर युवा महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है।पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में महिलाओं की भूमिका केवल घरेलू दायरे तक सीमित नहीं रही है, बल्कि उन्होंने सामाजिक आंदोलनों, स्थानीय निकायों और विभिन्न योजनाओं में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसे में सरकार का यह कदम उसी बदलती तस्वीर को आगे बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में 28 अप्रैल को होने वाला विशेष सत्र बेहद अहम माना जा रहा है, जहां 'नारी शक्ति वंदन बिल' चर्चा के केंद्र में रहेगा। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार इस विधेयक को पेश करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आयोजित होने वाले इस सत्र को लेकर शासन स्तर पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है और सभी विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह बिल महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके जरिए महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सकता है। लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि नीति निर्माण का हिस्सा बनाया जाए। धामी सरकार इस बिल को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं, विपक्ष भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है और इसके प्रावधानों को लेकर सवाल उठाने की तैयारी में है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि विधानसभा के भीतर इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिलेगी।

नारी शक्ति वंदन बिल आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी डाल सकता है असर

यह विधेयक केवल सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी असर डाल सकता है। महिला मतदाताओं की भूमिका लगातार निर्णायक होती जा रही है और ऐसे में सरकार की यह पहल राजनीतिक दृष्टि से भी अहम मानी जा रही है। खासकर पहाड़ी राज्यों में, जहां महिलाओं की भागीदारी सामाजिक ढांचे की रीढ़ मानी जाती है, यह बिल दूरगामी प्रभाव छोड़ सकता है। सत्र के दौरान महिला सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा और स्वरोजगार से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाए जाने के संकेत हैं। सरकार इन क्षेत्रों में अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को सामने रख सकती है, वहीं विपक्ष इन दावों की पड़ताल करते हुए जमीनी सच्चाई को मुद्दा बना सकता है। इससे सदन के भीतर गंभीर और व्यापक चर्चा की संभावना बन रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच इस विधेयक को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं। स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायत स्तर पर सक्रिय महिलाओं को उम्मीद है कि इससे उन्हें निर्णय प्रक्रिया में अधिक अधिकार और प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह पहल स्थानीय स्तर पर नेतृत्व को बढ़ावा देने का माध्यम भी बन सकती है। सरकार बिल को व्यापक समर्थन दिलाने के लिए सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों से भी संपर्क में है। साथ ही, सत्र के दौरान कुछ और महिला-केंद्रित घोषणाएं किए जाने की संभावना जताई जा रही है, जिससे इस पहल को और मजबूती मिल सके। वहीं विपक्ष भी इसे लेकर अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की संभावना है, ताकि बिल पर सहमति बनाने की कोशिश की जा सके। उधर, महिला संगठनों ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज तेज कर दी है और वे सरकार से ठोस प्रावधानों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सत्र से पहले ही माहौल पूरी तरह राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गया है।

डॉ. यशोधर मठपाल उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर

डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला

लोककला और प्रागैतिहासिक चित्रकला के संरक्षण के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम हैं। वे एक प्रतिष्ठित चित्रकार, इतिहासकार, पुरातत्वविद् और लोकसंस्कृति के गहरे अध्येता रहे हैं। उनका जीवन भारतीय परंपरा, विशेषकर हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को समझने, सहेजने और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए समर्पित रहा है।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

श्री यशोधर मठपाल का जन्म 6 जून 1939 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की भीकियासैन तहसील के नौला गांव में क्षेत्र में हुआ। बचपन से ही उन्हें चित्रकला और प्रकृति से गहरा लगाव था। पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता, लोकजीवन और परंपराओं ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ यशोधर मठपाल ने मनीला और रानीखेत में प्रारंभिक शिक्षा पूरी की इसके बाद लखनऊ से ललित कला में पांच वर्षीय डिप्लोमा कर स्वर्ण पदक हासिल किया। उसके बाद आगरा में पढ़ाई की। पूना से पुरात्व में पीएचडी हासिल की। उन्होंने उच्च शिक्षा के दौरान कला और इतिहास दोनों क्षेत्रों में रुचि विकसित की, जिससे आगे चलकर उनका कार्य बहुआयामी बना।

चित्रकला और कलात्मक योगदान

यशोधर मठपाल एक कुशल चित्रकार रहे हैं। उनकी कला में भारतीय परंपरा, लोकजीवन और प्रकृति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। उन्होंने विशेष रूप से प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के अध्ययन और पुनर्निर्माण में उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले प्राचीन गुफा चित्रों का अध्ययन किया और उनकी प्रतिकृतियाँ तैयार कीं, जिससे आम लोगों को इन दुर्लभ कलाकृतियों को समझने का अवसर मिला।

प्रागैतिहासिक शैलचित्रों का संरक्षण

उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत की प्राचीन शैलचित्र परंपरा के संरक्षण में रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश के भीमबेटका जैसे विश्व प्रसिद्ध शैलाश्रयों का गहन अध्ययन किया। इन चित्रों के माध्यम से उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि हजारों वर्ष पहले के मानव का जीवन, उसकी सोच और उसकी संस्कृति कैसी थी। उन्होंने न केवल इन चित्रों का अध्ययन किया बल्कि उन्हें संरक्षित करने और उनके महत्व को जन-जन तक पहुंचाने का भी प्रयास किया।

लोक संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण

यशोधर मठपाल ने उत्तराखंड की लोकसंस्कृति, रीति-रिवाजों, त्योहारों और लोककला को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने देखा कि आधुनिकता के प्रभाव से पारंपरिक कला और संस्कृति धीरे-धीरे लुप्त हो रही है, इसलिए उन्होंने इसे बचाने के लिए ठोस कदम उठाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने भीमताल (नैनीताल) में "फोक कल्चर म्यूजियम" की स्थापना की। इस संग्रहालय में उत्तराखंड की लोककला, हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र, आभूषण और अन्य सांस्कृतिक वस्तुओं का संग्रह किया गया है। उनके द्वारा स्थापित संग्रहालय आज एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ आने वाले लोगों को उत्तराखंड की समृद्ध परंपरा और इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यह संग्रहालय केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत प्रयास है-अपनी जड़ों को पहचानने और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक श्री मठपाल एक लेखक और शोधकर्ता भी रहे हैं। उन्होंने भारतीय प्रागैतिहासिक कला, लोकसंस्कृति और इतिहास पर कई पुस्तकें और शोधपत्र लिखे हैं। उनके लेखन में गहन अध्ययन, अनुभव और संवेदनशील दृष्टिकोण दिखाई देता है। उनकी पुस्तकों के माध्यम से छात्रों, शोधकर्ताओं और आम पाठकों को भारतीय संस्कृति की गहराई को समझने का अवसर मिलता है।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान

यशोधर मठपाल के कार्यों को न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय शैलचित्रों और लोकसंस्कृति पर व्याख्यान दिए। उनकी मेहनत और समर्पण के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया।

पुरस्कार और सम्मान

उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार और विभिन्न संस्थाओं ने उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया है। वे उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने अपने कार्य से भारतीय सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिलाई।

व्यक्तित्व और प्रेरणा

श्री यशोधर मठपाल का व्यक्तित्व अत्यंत सरल, विनम्र और समर्पित रहा है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि यदि किसी व्यक्ति में अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम और समर्पण हो, तो वह समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कला, इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। श्री यशोधर मठपाल केवल एक कलाकार या इतिहासकार नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने कार्यों से अतीत और वर्तमान के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण किया है। उन्होंने यह साबित किया कि हमारी परंपराएँ और सांस्कृतिक धरोहर केवल अतीत की चीजें नहीं हैं, बल्कि वे हमारी पहचान और भविष्य की दिशा भी निर्धारित करती हैं। उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर है, जिसे सदैव याद रखा जाएगा।

लेखक विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।

बंगाल-तमिलनाडु में रिकॉर्ड मतदान का नया अध्याय

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 23 अप्रैल 2026 को हुए विधानसभा चुनाव के पहले चरण ने भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल में 92.54% और तमिलनाडु में 84.69% मतदान दर्ज कर मतदाताओं ने अभूतपूर्व भागीदारी दिखाई। खास बात यह रही कि बंगाल, जो कभी चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता था, वहां इस बार मतदान अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा। बढ़ी हुई वोटिंग के पीछे सख्त सुरक्षा व्यवस्था, मतदाता सूची पुनरीक्षण और लोगों की बढ़ती जागरूकता को प्रमुख कारण माना जा रहा है। महिलाओं, युवाओं और प्रवासी मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी ने इस उत्साह को और मजबूत किया। कई जिलों में 90% से अधिक मतदान दर्ज हुआ, जो बड़े जनादेश का संकेत देता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इतनी बड़ी संख्या में मतदान अक्सर बदलाव की आहट भी देता है। अब नजर चुनाव परिणामों पर है, जो तय करेंगे कि यह रिकॉर्ड भागीदारी सियासी समीकरणों को किस हद तक प्रभावित करती है। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट।

भारतीय लोकतंत्र ने एक बार फिर अपनी जीवंतता और मजबूती का प्रभावशाली परिचय दिया है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 23 अप्रैल 2026 को हुए विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिस तरह का ऐतिहासिक मतदान दर्ज हुआ, उसने न केवल पुराने आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि लोकतंत्र में जनता के विश्वास को भी और गहरा किया है। बंगाल में 92.54 प्रतिशत और तमिलनाडु में 84.69 प्रतिशत मतदान यह दर्शाता है कि मतदाता अब पहले से अधिक जागरूक, सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। खास बात यह रही कि पश्चिम बंगाल, जो कभी चुनावी हिंसा के लिए चर्चा में रहता था, वहां इस बार मतदान अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। यह बदलाव प्रशासनिक सतर्कता और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था का संकेत देता है।

अगर पिछले चुनावों से तुलना करें, तो यह उछाल और भी महत्वपूर्ण नजर आता है। 2021 में बंगाल के पहले चरण में 81.16 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो इस बार 92 प्रतिशत के पार पहुंच गया। वहीं तमिलनाडु में 2011 का 78.29 प्रतिशत रिकॉर्ड टूटकर 84.69 प्रतिशत तक पहुंच गया। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिलीं, जो देर शाम तक जारी रहीं। महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही, वहीं प्रवासी श्रमिकों ने भी बड़ी संख्या में लौटकर मतदान किया। इससे यह स्पष्ट है कि अब मतदाता केवल दर्शक नहीं, बल्कि लोकतंत्र के सक्रिय भागीदार बन चुके हैं। वोट प्रतिशत बढ़ाने के करण जो निकल कर सामने आए उसमें विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में हुए बदलावों ने लोगों को अधिक सजग बनाया। नाम कटने की आशंका ने भी लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही चुनाव आयोग की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था ने मतदाताओं का भरोसा बढ़ाया। तमिलनाडु में 5.73 करोड़ मतदाताओं में से 84.69 प्रतिशत ने वोट डाले। करूर जिला 91 प्रतिशत से अधिक मतदान के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि चेन्नई जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 83 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज हुआ।

क्या रिकॉर्ड वोटिंग बदल देगी सियासी समीकरण?

इतिहास बताता है कि जब मतदान प्रतिशत में बड़ा उछाल आता है, तो राजनीतिक बदलाव की संभावना भी बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल में 1967, 1977 और 2011 के चुनाव इसके उदाहरण हैं, जब भारी मतदान के साथ सत्ता परिवर्तन हुआ। इस बार 90 प्रतिशत से अधिक मतदान ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बंगाल में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है। हालांकि इसका जवाब नतीजे ही देंगे, लेकिन संकेत साफ हैं कि मतदाता इस बार सोच-समझकर फैसला ले रहे हैं। अधिक मतदान केवल उत्साह नहीं, बल्कि बदलाव की चाह और मौजूदा व्यवस्था के प्रति असंतोष का संकेत भी हो सकता है। तमिलनाडु में भी पारंपरिक राजनीति के बीच नए समीकरण चुनाव को रोचक बना रहे हैं।

जिलों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान, लोकतंत्र की मजबूत नींव

चुनाव आयोग के अनुसार कई जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज हुआ। पश्चिम बंगाल में दक्षिण दिनाजपुर, कूचबिहार, बीरभूम और जलपाईगुड़ी जैसे जिलों ने नया रिकॉर्ड बनाया। तमिलनाडु में भी करूर, सलेम, इरोड और धर्मपुरी जैसे जिलों में भारी मतदान दर्ज किया गया। शहरी क्षेत्रों में भले ही प्रतिशत थोड़ा कम रहा, लेकिन वह भी संतोषजनक स्तर पर रहा। पूरे चुनाव के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और कहीं से भी किसी बड़ी अप्रिय घटना की खबर

नहीं आई। मतदान केंद्रों पर उमड़ी भीड़ इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले चरण के रिकॉर्ड मतदान को भारतीय लोकतंत्र की बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यह अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है, जो मतदाताओं की बढ़ती जागरूकता और भरोसे को दर्शाता है। चुनाव आयोग के अनुसार दोनों राज्यों में भारी संख्या में लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया, जहां कई जिलों में 90% से अधिक वोटिंग दर्ज हुई। कड़े सुरक्षा इंतजामों और बेहतर व्यवस्थाओं ने मतदाताओं को निर्भय माहौल दिया। यह रिकॉर्ड मतदान केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि जनता की बढ़ती राजनीतिक समझ, भागीदारी और विश्वास का प्रतीक है। आने वाले नतीजे तय करेंगे कि यह जनभागीदारी किस दिशा में सियासत को मोड़ती है, लेकिन इतना तय है कि लोकतंत्र की यह ऊर्जा लंबे समय तक महसूस की जाएगी। ज्ञानेश कुमार ने इस उत्साह के लिए सभी मतदाताओं का आभार जताया और इसे लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक बताया।

केदारनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं पर गलत जानकारी फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई

चारधाम यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं तथ्यहीन सूचनाएं प्रसारित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। पूर्व में दर्ज प्रकरणों के क्रम में आज जनपद रुद्रप्रयाग के थाना सोनप्रयाग में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है। सोशल मीडिया मॉनीटरिंग के दौरान इंस्टाग्राम आईडी thecurlypoet के माध्यम से प्रसारित एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं को लेकर भ्रामक एवं निराधार दावे किए गए। वीडियो में यह गलत जानकारी दी गई कि एक वृद्ध श्रद्धालु को स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद प्रशासन द्वारा सहायता नहीं दी गई तथा वीआईपी प्रोटोकॉल के चलते सामान्य श्रद्धालुओं की अनदेखी की जा रही है। जबकि वास्तविकता में दिनांक 22.04.2026 को गुजरात निवासी एक श्रद्धालु की तबीयत खराब होने पर प्रशासन द्वारा तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केदारनाथ पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। तत्पश्चात प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए हेलीकॉप्टर के माध्यम से शव को गुप्तकाशी भेजा गया।

उक्त वीडियो के माध्यम से तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर आमजन को भ्रमित करने एवं प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया, जिस पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चार धाम यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना, अफवाह या दुष्प्रचार पर तत्काल, सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, अन्य संदिग्ध वीडियो एवं सोशल मीडिया कंटेंट की भी सतत निगरानी की जा रही है और उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई के दायरे में लाया जा रहा है। स्पष्ट किया जाता है कि चार धाम यात्रा की गरिमा, श्रद्धालुओं की आस्था एवं उत्तराखंड की छवि के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। भ्रामक सूचना फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की यह प्रक्रिया लगातार, सख्ती और पूरी सतर्कता के साथ जारी रहेगी।

केदारनाथ हेली शटल सेवा हेतु ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न, पारदर्शिता और सुव्यवस्था से यात्रियों को मिली सुविधा

15 अप्रैल 2026 को सायं 6:00 बजे से श्री केदारनाथ हेली शटल सेवा के लिए 22 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 की अवधि हेतु ऑनलाइन बुकिंग के हेली यात्रा बुकिंग पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ की गई। निर्धारित अवधि के लिए कुल 31,450 सीटों की बुकिंग खोली गई, जिनमें 10,855 टिकटों के माध्यम से सभी 31,450 सीटों की सफलतापूर्वक बुकिंग की गई। ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया की समीक्षा के लिए टूरिस्ट हेल्पलाइन कॉल सेंटर, उत्तराखंड पर्यटन द्वारा 565 रैंडम कॉल्स की गई। इस विश्लेषण में पाया गया कि आईआरसीटीसी की बुकिंग में यात्रियों द्वारा उपयोग किए गए 10,859 मोबाइल नंबरों में से 4,400 नंबर वास्तविक यात्रियों से मेल खाते पाए गए। साथ ही लगभग 51 प्रतिशत बुकिंग स्वयं यात्रियों द्वारा की गई, जबकि शेष 49 प्रतिशत बुकिंग अन्य माध्यमों से संपन्न हुई। बुकिंग प्रक्रिया के दौरान प्रथम टिकट सायं 6:02 बजे तथा अंतिम टिकट सायं 7:28 बजे बुक की गई। सायं 6:10 बजे से 6:32 बजे के मध्य पीक बुकिंग दर्ज की गई, जिसमें 6:10 बजे 849 बुकिंग दर्ज की गई और 6:32 बजे तक बुकिंग संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। राज्यवार आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र से सर्वाधिक 1708 बुकिंग, उत्तर प्रदेश से 1243, दिल्ली से 867, तेलंगाना से 864, कर्नाटक से 801 तथा गुजरात से 700 बुकिंग दर्ज की गई।

बुकिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाए रखने हेतु प्रति यूजर अधिकतम 2 बुकिंग एवं अधिकतम 12 सीट बुक करने की अनुमति दी गई। एक आईपी से अधिकतम 5 यूजर आईडी द्वारा बुकिंग की जा सकती है तथा एक बुकिंग में अधिकतम 6 यात्रियों को शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार एक यूजर द्वारा कुल अधिकतम 12 यात्रियों की बुकिंग संभव है। वर्तमान तक 510 बुकिंग आईडी के सापेक्ष कुल 913 सीटों के लिए कैंसलेशन दर्ज किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित यह बुकिंग प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न की गई है, जिससे यात्रियों को सुगम, सुरक्षित एवं विश्वसनीय यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

ज्ञान, जुनून और जनसेवा का संगम

प्रोफेसर (डॉ.) तिलोत्तमा सिंह

प्रोफेसर (डॉ.) तिलोत्तमा सिंह
प्रोफेसर (एचआर विश्लेषक)
उत्तराँचल संस्थान प्रबंधन
उत्तराँचल विश्वविद्यालय देहरादून

अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा के बारे में बताएं?

मेरा जन्म और पालन-पोषण उत्तराखंड में हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून से पूरी हुई। शुरुआत से ही मेरी रुचि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रही, जिसके चलते मैंने उच्च शिक्षा के लिए चंडीगढ़ का रुख किया। वहां मैंने विधी के साथ-साथ अर्थशास्त्र में ऑनर्स किया। अपने ज्ञान और कौशल को और विकसित करने के उद्देश्य से मैंने मास कम्युनिकेशन में व्यावसायिक पाठयक्रम भी किया, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके बाद मैंने एमबीए में गोल्ड डिस्टिंक्शन हासिल की। शिक्षा का यह सफर यहीं नहीं रुका- मैंने उत्तरांचल विश्वविद्यालय में प्रबंधन एवं वाणिज्य विभाग की विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए भी अपने कौशल को लगातार निखारा और आईआईएम से एचआर एनालिटिक्स में डिस्टिंक्शन प्राप्त किया। वर्तमान में, मैं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हूं। एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन संस्था के साथ सीरीज एडिटर के रूप में जुड़ी हूं और भारत तथा विदेशों में महिला विकास से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स में योगदान दे रही हूं। एक वैश्विक SDG एडवोकेट के रूप में मेरे नाम 20 से अधिक पुस्तकें भी प्रकाशित हैं।

आपके प्रोफेशन के बारे में बताएं या आप इस क्षेत्र में कैसे आए और किससे प्रेरित हुए?

मेरे जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे पिता रहे हैं। उनसे ही मैंने सीख लिया कि अपने करियर को समझदारी से चुनना और उसमें निरंतर आगे बढ़ना कितना महत्वपूर्ण होता है। सौभाग्य से मुझे अपने करियर के अलग-अलग विकल्पों को समझने और चुनने की आजादी मिली और इसी के साथ मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान लीला केम्पिंस्की में अपने करियर की शुरुआत की, जहां मैं ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट से जुड़ी रही। शुरुआत से ही मानव संसाधन को विकसित करना और उनकी क्षमताओं को निखारना मेरी रुचि का केंद्र रहा। इसी रुचि ने मुझे शिक्षा के क्षेत्र की ओर प्रेरित किया, जहां मैंने सीधे छात्रों के साथ काम करना शुरू किया। इस सफर की शुरुआत 'टिच फॉर इंडिया' के साथ हुई, जिसके बाद मैंने सरकारी स्कूलों की छात्राओं के साथ काम किया, चाहे वह होसनाबाद की छात्राएं हों, या वर्चुअल माध्यम से बांग्लादेश और नाइजीरिया की छात्राएं। पिछले 14 वर्षों से मैं शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय हूं और आईएमएस, एमिटी विश्वविद्यालय और वर्तमान में उत्तराँचल विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ कार्य कर चुकी हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि छात्रों के साथ जुड़कर उन्हें आगे बढ़ते देखना है। जब वे एक जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज में सार्थक योगदान देते हैं, तो वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इसी सोच के साथ हम छात्र समितियों के माध्यम से सामाजिक परियोजनाओं पर भी कार्य कर रहे हैं और इस पहल को वैश्विक स्तर तक ले जाने का लक्ष्य रखते हैं। मुझे विश्वास है कि ईश्वर की कृपा और हमारी सामूहिक कोशिशों से हम समाज में एक सकारात्मक और मजबूत बदलाव जरूर ला पाएंगे।

आपकी उपलब्धियों के बारे में बताएं, आपने क्या काम किया है?

मेरे पेशेवर सफर में शिक्षा, नेतृत्व और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में निरंतर योगदान मेरी प्रमुख उपलब्धि रही है। वर्तमान में मैं उत्तरांचल प्रबंधन संस्थान में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूं, जो उत्तराँचल विश्वविद्यालय का हिस्सा है। इस भूमिका में मैं फैकल्टी कोऑर्डिनेशन, पाठयक्रम विकास और छात्र कल्याण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का नेतृत्व कर रही हूं। मेरे नेतृत्व में विभाग ने अपने शैक्षणिक पाठयक्रम को उद्योग 4.0 और 5.0 की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया है, जिससे छात्रों को आधुनिक और व्यावहारिक शिक्षा मिल सके। इसके साथ ही, मैंने संस्थान के लिए एक रणनीतिक रोडमैप तैयार करने में योगदान दिया है, जिसमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, NIRF रैंकिंग में सुधार और CESIM जैसे बिजनेस सिमुलेशन टूल्स का समावेश शामिल है। मैं All India Management Association (AIMA) की सक्रिय सदस्य भी हूं, जहां मैं इंडस्ट्री और अकादमिक क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर काम कर रही हूं। इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, नेटवर्किंग और इंडस्ट्री कनेक्ट के माध्यम से छात्रों को वैश्विक अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर, मेरा उद्देश्य शिक्षा को केवल सैद्धांतिक न रखकर उसे व्यावहारिक, नवाचार-आधारित और समाज के लिए उपयोगी बनाना रहा है।

आपके भविष्य की योजनाओं के बारे में बताएं?

मेरी भविष्य की योजनाएं मुख्य रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रभावशाली और परिवर्तनकारी नेतृत्व स्थापित करने के साथ-साथ मानव-केंद्रित प्रबंधन के वैश्विक विमर्श को आगे बढ़ाने पर केंद्रित हैं। शोध और अकादमिक क्षेत्र में मेरा लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाले शोध कार्य करना है, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्यस्थल पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव और महिला उद्यमियों के सामने आने वाली सामाजिक चुनौतियों जैसे विषयों पर। मैं अपने शोध को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित करने के साथ-साथ "Healing Algorithm" जैसे विषय पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखने की योजना भी रखती हूं, जिससे तकनीक और मानव मूल्यों के संतुलन को बेहतर तरीके से समझाया जा सके। पेशेवर स्तर पर, मैं अपने एचआर एनालिटिक्स के अनुभव का उपयोग करते हुए संगठनों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान मार्गदर्शन देना चाहती हूं, ताकि वे डेटा-आधारित कार्यप्रणाली के साथ-साथ मानव मूल्यों और कल्याण को भी संतुलित रख सकें। इसके साथ ही, मेरा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करना है। मैं एक मजबूत मेंटरशिप फ्रेमवर्क तैयार करना चाहती हूं, जो उभरती हुई महिला शोधकर्ताओं और पेशेवरों को मार्गदर्शन दे सके। भविष्य में मैं एक NGO के माध्यम से विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं के विकास के लिए कार्य करना चाहती हूं, क्योंकि वे समाज और परिवार की आधारशिला हैं। मैं अपने गृह राज्य उत्तराखंड से इस पहल की शुरुआत करते हुए नीति निर्माण, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में योगदान देना चाहती हूं, ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सके। अंततः मेरा उद्देश्य यह है कि शिक्षा, तकनीक और सामाजिक विकास के माध्यम से एक ऐसा संतुलित और समावेशी समाज बनाया जाए, जहां आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक समानता भी सुनिश्चित हो सके।

आप हमारी पत्रिका के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?

मैं इस पत्रिका के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं, शिक्षार्थियों, उभरते नेतृत्वकर्ताओं और समाज के उन सभी लोगों से जुड़ना चाहती हूं, जो सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरा संदेश विशेष रूप से महिलाओं और उन सभी व्यक्तियों के लिए है, जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। आज के इस प्रतिस्पर्धी और तेजी से बदलते अल्फा वर्ल्ड में यह आवश्यक है कि हम सभी मिलकर, सहयोग और सहभागिता के माध्यम से एक समावेशी और सशक्त समाज का निर्माण करें। इस मंच के माध्यम से मुझे अपने विचार साझा करने का अवसर देने के लिए मैं दिव्य हिमगिरि के संपादक कुँवर राज अस्थाना और पूनम आर्य का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूं, जो समाज को जोड़ने वाले और समुदाय-आधारित सार्थक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। अंत में, मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि हम सभी मिलकर कार्य करें, तो हम निश्चित रूप से एक बेहतर, समान और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं।

जन सामान्य मंच का बड़ा ऐलान: अब चुनाव में वोट की चोट से होगा 'स्वार्थ की राजनीति' का अंत

उत्तराखंड में 'राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा' की तैयारी, ब्राह्मण महासंघ ने फूंका चुनावी बिगुल

उत्तराखंड की राजधानी में सवर्ण समाज ने अपनी उपेक्षा और मौजूदा राजनैतिक नीतियों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। शुक्रवार को उत्तराखंड ब्राह्मण समाज महासंघ (पंजी.) के सौजन्य में 'जन सामान्य मंच' ने उज्जवल रेस्टोरेंट में एक विशाल 'सवर्ण चिंतन गोष्ठी' का आयोजन किया। इस बैठक में न केवल ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए, बल्कि अधिवक्ता, पत्रकार और किसान संघों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर भविष्य की राजनैतिक दिशा बदलने की शपथ ली।

गोष्ठी में वक्ताओं ने दो-टूक शब्दों में कहा कि वर्तमान राजनीति केवल सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने का काम कर रही है। नेताओं की नीतियां देश की अखंडता के लिए खतरा बन गई हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं। चर्चा के दौरान यह बात प्रमुखता से उभरी कि आज 'कॉमन मैन' यानी उस जन सामान्य की सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिसे किसी विशेष कोटे या दर्जे का लाभ नहीं मिलता। मंच के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र कुमार पांडे ने संगठन की नींव और उद्देश्यों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यह मंच उन लोगों की आवाज बनेगा जिनके अधिकारों की बात आज की राजनीति में गौण हो चुकी है। पांडे ने जोर दिया कि सामाजिक समरसता और प्रकृति की रक्षा के साथ-साथ आपसी सद्भाव को बचाना ही इस संघर्ष का असली मकसद है।

इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जुगल किशोर तिवारी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए 'राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा' के गठन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब समाज को इन परंपरागत राजनैतिक दलों के जाल से बाहर निकलना होगा। गोष्ठी में मौजूद सभी समूहों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाने वाले दलों का सामाजिक स्तर पर बहिष्कार किया जाएगा। मंच ने विशेष रूप से एससी-एसटी एक्ट, आरक्षण की वर्तमान स्थिति और यूजीसी रेगुलेशन के नाम पर फैलाई जा रही अराजकता को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। ब्राह्मण महासंघ ने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनावों में सवर्ण समाज केवल उन्हीं विकल्पों पर विचार करेगा जो उनके हितों और सामाजिक समानता की बात करेंगे, अन्यथा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार एक ठोस रणनीति के रूप में अपनाया जाएगा। गोष्ठी का सफल संचालन डॉ. वी.डी.शर्मा ने किया और अध्यक्षता पंडित विजेंद्र प्रसाद ममगई ने की। उपरोक्त के अतिरिक्त आज की इस सवर्ण चिंतन गोष्ठी में वरिष्ठ समाजसेवी पंडित लालचंद शर्मा, एस.पी.पाठक, विनोद नौटियाल, किसान नेता सुरेंद्र दत्त शर्मा, शशि कुमार शर्मा, मनमोहन शर्मा, अरुण कुमार शर्मा, अरुण शर्मा (किसान नेता), सिद्धनाथ उपाध्याय, अश्वनी मुद्गल एडवोकेट, राकेश पंडित (पार्षद) आदि ने भी संबोधित करते हुए अपने अपने विचार रखें।

गौरतलब है कि उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों में पदोन्नति में आरक्षण और एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग को लेकर सामान्य और ओबीसी संगठनों का विरोध मुखर रहा है। साल 2020 के आसपास भी प्रदेश में इस मुद्दे पर बड़े आंदोलन देखे गए थे, जिससे सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था।

डिजिटल क्रांति और एआई के दौर में स्याही से पिक्सल तक बदलती हिंदी पत्रकारिता

अजय कुमार,
वरिष्ठ पत्रकार

हिंदी पत्रकारिता का इतिहास गवाह है कि इसने हमेशा समाज की धड़कनों को शब्दों के जरिए कागज पर उतारा है, लेकिन पिछले एक दशक में इस सफर ने जो मोड़ लिया है, वह किसी महाकाव्य के अध्याय बदलने जैसा है। कल तक सुबह के अखबार की दस्तक और चाय की चुस्की के साथ शुरू होने वाला सूचनाओं का सिलसिला अब अंगूठे के एक स्वाइप पर सिमट गया है। प्रिंट मीडिया, जो कभी सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा करने का इकलौता जरिया था, आज डिजिटल और वीडियो प्लेटफॉर्म्स की सुनामी के बीच अपनी जमीन बचाने और खुद को नए सांचे में ढालने की जद्दोजहद कर रहा है। यह बदलाव केवल तकनीक का नहीं है, बल्कि यह पत्रकारिता के मिजाज, उसकी भाषा और सबसे महत्वपूर्ण, उसके सरोकारों के बदलने की कहानी है। जब हम प्रिंट से डिजिटल और फिर यूट्यूब के इस त्रिकोणीय सफर को देखते हैं, तो आंकड़ों की जुबानी इस बदलाव की भयावहता और भव्यता दोनों समझ आती है। एक दौर था जब हिंदी के प्रमुख अखबारों की प्रसार संख्या करोड़ों में हुआ करती थी, लेकिन हालिया वर्षों में 'डिजिटल फर्स्ट' के मंत्र ने इस समीकरण को उलट दिया है। आज भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 80 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा अपनी खबरों के लिए केवल सोशल मीडिया और यूट्यूब पर निर्भर है। प्रिंट के दौर में 'डेडलाइन' का एक अनुशासन था। संपादक के पास समय होता था कि वह खबर की तह तक जाए, उसे परखे और फिर पाठकों के सामने परोसे। लेकिन आज के 'ब्रेकिंग न्यूज' और 'वायरल कल्चर' ने उस ठहराव को छीन लिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खबर की रफ्तार को तो पंख लगा दिए, लेकिन इस रफ्तार में कहीं न कहीं वह गहराई पीछे छूट गई जो कभी हिंदी लेखनी की पहचान हुआ करती थी। इस संक्रमण काल में सबसे अधिक प्रभावित हुई है पत्रकारिता की भाषा और उसका अर्थशास्त्र। जो हिंदी कभी साहित्यिक मर्यादाओं और व्याकरण की शुचिता से बंधी थी, वह अब 'क्लिक' पाने की मजबूरी में हिंग्लिश और बोलचाल की सरलता की ओर झुक गई है। डिजिटल स्क्रीन पर पाठक की एकाग्रता का समय (अटेंशन स्पैन) मात्र 8 से 12 सेकंड रह गया है, इसलिए अब लंबे विश्लेषणों की जगह 'इनफोग्राफिक्स' और 'शॉर्ट्स' ने ले ली है। यूट्यूब जैसे मंचों ने तो पत्रकारिता के व्याकरण को ही उलट दिया है। यहाँ अब 'एंकर' और 'संवाददाता' के बीच की लकीर मिट गई है। हर वह व्यक्ति जिसके पास कैमरा और इंटरनेट है, वह खुद को एक मीडिया संस्थान के रूप में पेश कर रहा है। इससे एक ओर तो मुख्यधारा के मीडिया से छूटे हुए मुद्दे सामने आए हैं, लेकिन दूसरी ओर सतही ज्ञान और सनसनी का एक ऐसा बाजार सज गया है जिसने गंभीर विमर्श को हाशिए पर धकेल दिया है। अब इस परिदृश्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रवेश एक नए और चुनौतीपूर्ण युग की आहट है। न्यूजहॉल के भीतर अब एआई केवल डेटा विश्लेषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खबरों को लिखने, अनुवाद करने और यहाँ तक कि न्यूज एंकरिंग तक में दखल दे रहा है। एआई ने पत्रकारिता की कार्यक्षमता को तो कई गुना बढ़ा दिया है, लेकिन इसके साथ ही इसने 'मानवीय संवेदना' और 'नैतिकता' पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जब एक मशीन खबर लिखती है, तो वह तथ्यों को जोड़ तो सकती है, लेकिन वह उस मानवीय पीड़ा को शब्द नहीं दे सकती जो एक रिपोर्टर मौके पर महसूस करता है। एआई का सबसे खतरनाक प्रभाव 'डीपफेक' के रूप में सामने आ रहा है, जहाँ 70 प्रतिशत से अधिक उपयोगकर्ता असली और नकली वीडियो में फर्क नहीं कर पाते। एल्गोरिदम अब यह तय कर रहे हैं कि आप क्या पढ़ेंगे, समाज में 'फिल्टर बबल' बन रहे हैं यानी व्यक्ति केवल अपनी पसंद की कट्टर सोच वाली खबरें ही देख पाता है। आर्थिक मोर्चे पर भी यह बदलाव किसी भूकंप से कम नहीं है। प्रिंट मीडिया का जो विज्ञापन राजस्व कभी 40 प्रतिशत की दर से बढ़ता था, सिमटकर डिजिटल दिग्गजों की जेब में जा रहा है। डिजिटल मीडिया में राजस्व का मॉडल अभी भी प्रयोग के दौर से गुजर रहा है। 'पेवॉल' और 'सब्सक्रिप्शन' जैसी कोशिशें हिंदी पट्टी में अभी भी संघर्ष कर रही हैं। नतीजा यह है कि राजस्व के लिए मीडिया घरानों को अब 'स्पॉन्सर्ड कंटेंट' का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे निष्पक्षता की दीवारें कमजोर हुई हैं। यूट्यूब ने एक नए अर्थशास्त्र को जन्म दिया है, जहां 'व्यूज' और 'वॉच टाइम' ही सबसे बड़ी मुद्रा है। जब खबर का महत्व उसकी सामाजिक उपयोगिता से नहीं बल्कि उसके 'वायरल' होने की क्षमता से तय होने लगे, तो यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए खतरे की घंटी है। बावजूद इसके, इस बदलाव ने पत्रकारिता को दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के वातानुकूलित कमरों से निकालकर छोटे शहरों और कस्बों की गलियों तक पहुँचा दिया है। आज ग्राउंड रिपोर्टिंग का अर्थ केवल बड़े चौनलों की ओबी वैन नहीं, बल्कि एक मोबाइल हाथ में थामे वह निर्भीक पत्रकार भी है जो सत्ता से सीधे सवाल पूछ रहा है। भविष्य की हिंदी पत्रकारिता अब एक 'हाइब्रिड' मॉडल की ओर बढ़ रही है। अखबार अब केवल सूचना के वाहक नहीं, बल्कि गहन विश्लेषण के दस्तावेज बन रहे हैं। एआई के दौर में असली चुनौती केवल तकनीक को अपनाने की नहीं है, बल्कि उस 'साख' को बचाने की है जो मशीनी शोर में कहीं दब गई है। हिंदी पत्रकारिता का यह सफर स्याही से पिक्सल और अब एआई तक तो पहुंच गया है, इसकी सार्थकता तभी बनी रहेगी जब यह 'सत्य' की उस मशाल को जलाए रखेगा जिसे लेकर भारतेन्दु हरिश्चंद्र और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पुरोधाओं ने इसे शुरू किया था। तकनीक और मशीनें केवल उपकरण हो सकती हैं, पत्रकारिता की आत्मा तो हमेशा मानवीय विवेक और जनसरोकार ही रहेगी।

अयोध्या में उत्तराखंड का भव्य अतिथि गृह: श्रद्धालुओं के लिए नई सौगात

देश की धार्मिक राजधानी अयोध्या में उत्तराखंड सरकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल शुरू की है। अयोध्या-फैजाबाद हाईवे पर प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह अब हकीकत का रूप लेता दिख रहा है। लगभग 54,000 वर्ग फीट क्षेत्र में बनने वाला यह विशाल परिसर उत्तराखंड से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक भरोसेमंद ठिकाना बनेगा। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार के स्थल निरीक्षण के बाद परियोजना के क्रियान्वयन ने रफ्तार पकड़ ली है, जिससे साफ है कि सरकार इस योजना को लेकर पूरी गंभीरता से आगे बढ़ रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के पीछे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्पष्ट सोच और परिणामोन्मुख कार्यशैली दिखाई देती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धार्मिक पर्यटन को आर्थिक विकास से जोड़ने की जो रणनीति बनाई है, यह परियोजना उसी की एक मजबूत कड़ी है। चारधाम यात्रा को बेहतर प्रबंधन और सुविधाओं से जोड़ने के बाद अब सरकार अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों पर भी उत्तराखंड की पहचान स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि परियोजना गुणवत्ता, आधुनिकता और तय समयसीमा के मानकों पर खरी उतरे। सचिव आवास-राज्य संपत्ति जल्द मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें विस्तृत कार्ययोजना रिपोर्ट सौंपेंगें। निरीक्षण के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर पेयजल निगम राकेश चन्द्र तिवारी, राज्य संपत्ति विभाग से डॉ विनीता सिंह, वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी मुन्ना सिंह सहित संबधित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। रणनीतिक लोकेशन, आसान पहुंच प्रस्तावित अतिथि गृह की लोकेशन इसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। श्रीराम मंदिर से करीब 6.60 किलोमीटर और फैजाबाद शहर से 6.40 किलोमीटर की दूरी इसे अत्यंत सुविधाजनक बनाती है। अयोध्या एयरपोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी इसे देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए भी सुलभ बनाती है। वहीं लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज जैसे प्रमुख शहरों से सीधा संपर्क इसे धार्मिक पर्यटन का अहम केंद्र बना सकता है। देहरादून और नई दिल्ली से आने वाले यात्रियों के लिए भी यह एक प्रमुख पड़ाव होगा।

आम श्रद्धालुओं को बड़ी राहत

इस परियोजना की खासियत यह है कि इसे केवल वीआईपी सुविधाओं तक सीमित नहीं रखा गया है। आम श्रद्धालुओं के लिए किफायती दरों पर ठहरने की व्यवस्था इस योजना को जन-हितैषी बनाती है। चारधाम यात्रा की तर्ज पर यहां भी उत्तराखंड के श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित आवास मिलेगा। इससे अयोध्या यात्रा के दौरान ठहरने की समस्या काफी हद तक कम होगी और यात्रा अधिक सुगम बनेगी।

सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित होगा परिसर

सरकार की योजना इस अतिथि गृह को केवल ठहरने तक सीमित रखने की नहीं है, बल्कि इसे उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान के केंद्र के रूप में विकसित करने की है। यहां लोक कला, लोक संगीत, पारंपरिक उत्सव और सरस मेले जैसे आयोजन किए जाएंगे। इससे उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर मंच मिलेगा। साथ ही विवाह समारोह और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए भी यह परिसर उपयोगी साबित होगा, जिससे राजस्व के नए अवसर भी बनेंगे।

पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

अयोध्या में तेजी से बढ़ते धार्मिक पर्यटन के बीच यह परियोजना उत्तराखंड के लिए आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी साबित हो सकती है। लाखों श्रद्धालुओं के बीच उत्तराखंड की मौजूदगी इस अतिथि गृह के माध्यम से और मजबूत होगी। यह पहल "धार्मिक पर्यटन" और "संस्कृति कनेक्ट" के मॉडल को आगे बढ़ाते हुए राज्य के पर्यटन उद्योग को अप्रत्यक्ष रूप से नई गति देगी।

गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर

स्थल निरीक्षण के दौरान सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना उत्तराखंड की छवि से जुड़ी है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही की गुंजाइश नहीं है।

ड्रीम प्रोजेक्ट से बनेगा सांस्कृतिक सेतु

डॉ. आर. राजेश कुमार के अनुसार अयोध्या में बनने वाला उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच और प्रभावी कार्ययोजना का सशक्त उदाहरण है। यह परियोजना न केवल श्रद्धालुओं के लिए राहत लेकर आएगी, बल्कि उत्तराखंड को देश के धार्मिक और सांस्कृतिक मानचित्र पर नई मजबूती के साथ स्थापित करेगी। यह अतिथि गृह केवल एक इमारत नहीं बल्कि उत्तराखंड और अयोध्या के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम करेगा। यहां श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ-साथ उत्तराखंड की परंपराओं और संस्कृति को भी राष्ट्रीय पहचान मिलेगी।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि- युवा वर्ग अपने लक्ष्य को हासिल न होने पर मनोबल गिरने न दे। व्यवसाय में किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से कुछ दिक्कत रह सकती है, धैर्य और विवेक से काम लेना ही सही रहेगा। अपनी पारिवारिक व्यवस्था में बाहरी लोगों का दखल न होने दें। स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी-बड़ी परेशानी परेशान कर सकती है। भाग्यशाली रंग- ऑरेंज, भाग्यशाली अंक- 4

वृषभ राशि- सरकारी गतिविधियों से आपको बेहतरीन मुनाफा होने की संभावना है। बड़े-बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें और सही इलाज करवाएं। नौकरीपेशा लोगों पर बॉस और उच्च अधिकारियों का दबाव रहेगा। किसी भी परेशानी में जीवनसाथी और परिवार के लोगों की सलाह संजीवनी का काम करेगी। भाग्यशाली रंग- क्रीम, भाग्यशाली अंक- 3

मिथुन राशि- जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए कुछ संकल्प लेंगे और उन्हें दृढ़ता से निभाने की कोशिश भी करेंगे। बुजुर्गों और वरिष्ठ लोगों के आशीर्वाद व अनुभव से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। पड़ोसी या मित्रों के साथ फालतू के वाद-विवाद में न पड़ें। अपने आराम के लिए भी समय जरूर निकालें। भाग्यशाली रंग- जामुनी, भाग्यशाली अंक- 7

कर्क राशि- आपके महत्वपूर्ण कामों में घर के वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपके लिए भाग्योदय जैसा माहौल बनाएगा। हंसी-मजाक और मनोरंजन में भी समय बीतेगा। मेहनत के हिसाब से अच्छा परिणाम न मिलने पर तनाव को खुद पर हावी न होने दें, बल्कि सही समय का इंतजार करें। ज्यादा प्रचार-प्रसार करें। हल्का भोजन लें। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 2

सिंह राशि- महिलाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। दूसरों के निजी मामलों में उलझने से आपकी मान-हानि हो सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है। संतान की कोई नकारात्मक गतिविधि आपको परेशान कर सकती है, लेकिन शांति से समस्या सुलझाएं। बेवजह की आवाजाही से बचें। भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 9

कन्या राशि- ग्रह गोचर बहुत अनुकूल बना हुआ है, इनका भरपूर लाभ लें। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। बच्चों की पढ़ाई से आप संतुष्ट रहेंगे। फालतू खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल उन पर कटौती करना भी मुश्किल होगा। सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या बन सकती है। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 8

तुला राशि- आप नया घर या प्रॉपर्टी लेने की योजना बना रहे हैं, तो आपका फैसला बहुत सही है। कोई उधारी वाला लेनदेन न करें। विद्यार्थी सोचने-समझने में बहुत ज्यादा समय लगाकर हाथ आई उपलब्धियां खो सकते हैं। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से जल्द ही विवाह तक पहुंचने के अवसर मिल सकते हैं। जरूरी है। भाग्यशाली रंग- ऑरेंज, भाग्यशाली अंक- 5

वृश्चिक राशि- किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में अपने विचारों को सहज बनाए रखें। गुस्सा और अहम आपके काम बिगाड़ सकते हैं। इसलिए समय के अनुसार अपने स्वभाव में बदलाव लाएं। फिजूलखर्ची से बचें और बजट का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में पारिवारिक सहमति से विवाह की योजनाएं बन सकती हैं। भाग्यशाली रंग- नीला, भाग्यशाली अंक- 6

धनु राशि- कारोबार में बहुत ज्यादा काम रहेगा, लेकिन अभी लाभ की स्थिति सामान्य ही रहेगी। सरकारी कामकाज को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल रखने से रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। पति-पत्नी आपसी तालमेल से घर में सुखद और व्यवस्थित माहौल बनाए रखेंगे। कोई पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है। भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 2

मकर राशि- पारिवारिक माहौल में चल रहे तनाव को आपसी सहयोग से सुलझाने की कोशिश करें। दूसरों की मदद के साथ-साथ अपने कामों पर भी ध्यान दें। महिला वर्ग अपने करियर को लेकर फायदे की स्थिति में रहेगा। पति-पत्नी के बीच चल रहे तनाव का असर घर-परिवार पर भी पड़ सकता है। आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 1

कुंभ राशि- छोटे-मोटे निवेश से लाभ मिलेगा और भविष्य में कारोबार में वृद्धि भी होगी। लेकिन परिवार और कारोबार के बीच तालमेल बनाए रखना भी जरूरी होगा। पति-पत्नी के बीच सुखद सामंजस्य रहेगा और इससे घर की व्यवस्था भी अच्छी बनी रहेगी। ज्यादा मेहनत की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रह सकती है। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 6

मीन राशि- संतान से जुड़ी कुछ परेशानी रह सकती है। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा की वजह से तनावपूर्ण स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन सहयोगियों और कर्मचारियों का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लेनदेन से जुड़े मामलों में सतर्क रहें। दांपत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। लापरवाही न करें। खानपान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। भाग्यशाली रंग- गुलाबी, भाग्यशाली अंक- 7

EXPERIENCE HELI TOUR WITH

Himgiri Aviation & Tourism

SINCE 2018

3N/4D TOUR

A Unit of दिव्य हिमगिरि

केदार-बद्री यात्रा

BY HELICOPTOR

OPENING DATES

KEDARNATH	BADRINATH
22 April, 2026	23 April, 2026

ADVANCE BOOKING STARTS **BOOK NOW**

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

Contact for Reservation 8433456398, 9410353164

Email: himgiritourism@gmail.com

6 Municipal Road, Opp. Oxford School of Excellence, Dalanwala, Dehradun-248001 (UK)